

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारंकित प्रश्न सं. 863
जिसका उत्तर शुक्रवार, 26 जुलाई, 2024 को दिया जाना है

उच्चतम न्यायालय की पीठों के समक्ष लंबित मामले

863. श्री के. राधाकृष्णन :

क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस तथ्य पर ध्यान दिया है कि देश की न्यायिक व्यवस्था पर गंभीर परिणाम वाले कई मामले उच्चतम न्यायालय की विभिन्न संविधान पीठों के समक्ष लंबित हैं ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे मामलों के नाम, संविधान पीठ का प्रकार और लंबित रहने की अवधि का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा उनमें तेजी लाने में रुचि न दिखाना उपर्युक्त मामलों के लंबित रहने का कारण है. यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपचारात्मक कार्रवाई की गई है ; और

(घ) उच्चतम न्यायालय की स्थापना से लेकर आज तक संवैधानिक पीठों द्वारा कितने मामलों की सुनवाई की गई और उनका निपटान किया गया, दशक-वार संख्या दें ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) और (ख) : उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठों के समक्ष लंबित मामलों को “देश की विधिक प्रणाली के लिए गंभीर परिणाम होने” के आधार पर वर्गीकृत नहीं किया गया है। राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एनजेडीजी) पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, आज की तारीख तक उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठों के समक्ष लंबित मामलों की संख्या इस प्रकार है:

संविधान पीठ	लंबित मामलों की संख्या
पांच न्यायाधीशों की पीठ	35
सात न्यायाधीशों की पीठ	8
नौ न्यायाधीशों की पीठ	7
ग्यारह न्यायाधीशों की पीठ	0
11 से अधिक न्यायाधीश	0

राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एनजेडीजी) पर उपलब्ध सूचना के आधार पर, उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित मामलों का संविधान पीठ-वार विस्तृत विवरण, नाम और फाइल करने की तारीख सहित उपाबंध में दिया गया है ।

(ग) : उपर्युक्त उल्लिखित मामलों का निपटारा न्यायपालिका के अनन्य अधिकार क्षेत्र में है। तथापि, उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, संविधान पीठ के मामलों में प्रायः जटिल विधिक मुद्दे शामिल होते हैं और बहस कई दिनों से लेकर महीनों तक चल सकती है। इन मामलों में विधि के व्यापक विश्लेषण और विस्तृत जांच की आवश्यकता होती है। जिसके परिणामस्वरूप, ऐसे मामलों के त्वरित निर्णय के लिए कड़े मापदंड या निश्चित समयसीमा निर्धारित करना अव्यावहारिक है।

(घ) : उच्चतम न्यायालय की स्थापना से लेकर आज तक इसकी संवैधानिक पीठों द्वारा सुने और निपटाए गए मामलों की दशक-वार सूची निम्नानुसार है:

क्र. सं.	अवधि	संविधान पीठों द्वारा निपटाए गए मामलों की संख्या
1	1950-1959	440
2	1960-1969	956
3	1970-1979	292
4	1980-1989	110
5	1990-1999	157
6	2000-2009	138
7	2010-2019	70
8	2020-2024 (आज तक)	29
	कुल	2,192

उच्चतम न्यायालय की पीठों के समक्ष लंबित मामलों के संबंध में लोक सभा अतारंकित प्रश्न सं. 863 जिसका उत्तर 26.07.2024 को दिया जाना है के भाग (क) और भाग (ख) के उत्तर में विनिर्दिष्ट विवरण

डायरी नं.	मामला संख्या	फाइल करने की तारीख	पक्षकार का नाम
पांच न्यायाधीशों की पीठ			
25700 / 2023	रिट याचिका (सिविल) / 678 / 2023	01-07-2023	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार बनाम भारत संघ
31429 / 2013	रिट याचिका (सिविल) / 921 / 2013	01-10-2013	महिला और स्वास्थ्य के लिए एसएमए-संसाधन समूह बनाम भारत संघ
11168 / 2014	क्यूरेटिव पिटीशन (सिविल) / 106 / 2014	02-04-2014	डॉ. शेखर शेषाद्रि बनाम सुरेश कुमार कौशल
3658 / 2022	अवमानना याचिका (सिविल) / 91 / 2022	03-02-2022	पियाली रे चौधरी बनाम नारायण स्वरूप निगम
25917 / 2023	-	03-07-2023	अंजलि शर्मा बनाम भारत संघ
26252 / 2023	-	03-07-2023	भारतीय पशु कल्याण बोर्ड बनाम भारत संघ
46079 / 2023	पुनर्विलोकन याचिका (सिविल) / 1866 / 2023	03-11-2023	सुप्रियो उर्फ सुप्रिया चक्रवर्ती बनाम भारत संघ विधि और न्याय मंत्रालय
27935 / 2017	रिट याचिका (सिविल) / 880 / 2017	04-09-2017	एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स बनाम भारत संघ
7808 / 2018	रिट याचिका (सिविल) / 202 / 2018	05-03-2018	अश्विनी कुमार उपाध्याय बनाम भारत संघ
22311 / 2016	आपराधिक अपील / 1003 / 2017	05-07-2016	प्यारे लाल बनाम हरियाणा राज्य
30032 / 2009	सिविल अपील / 5965 / 2010	05-10-2009	भारतीय खाद्य निगम बनाम नव दुर्गा राइस मिल्स।
10730 / 2022	स्वप्रेरणा से रिट याचिका (आपराधिक) / 1 / 2022	06-04-2022	इनरी: फ्रेमिंग गाइडलाइन्स रिगार्डिंग पोर्टेशियल बनाम
17223 / 2015	रिट याचिका (सिविल) / 311 / 2015	06-05-2015	दीपक कुमार नाथ बनाम भारत संघ गृह मंत्रालय प्रतिनिधि
18396 / 2007	सिविल अपील / 9935 / 2014	06-07-2007	रांची एसोसिएशन बनाम भारत संघ और अन्य।
3900 / 2008	विशेष अनुमति याचिका (सिविल) / 3660 / 2008	08-02-2008	पंजाब राज्य बनाम साहिल मित्तल
28531 / 2019	सिविल अपील / 9486 / 2019	09-08-2019	सेंट्रल ऑर्गनाइजेशन फॉर रेलवे इलेक्ट्रिफिकेट बनाम मेसर्स ईसीआई एसपीआईसी एसएमओ एमसीएमएल (जेवी) एक संयुक्त उद्यम कंपनी
41794 / 2023	-	09-10-2023	सिडेना मुफद्दल सैफुद्दीन बनाम सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ दाऊदी बोहरा कम्युनिटी
12551 / 2020	-	10-06-2020	सुवर्णा पाका जग्गा राव बनाम चेत्रोलू लीला प्रसाद राव
10865 / 2000	रिट याचिका (सिविल) / 546 / 2000	10-07-2000	संविधान के अनुच्छेद 334 के संदर्भ में बनाम.....
18450 / 2021	रिट याचिका (सिविल) / 887 / 2021	10-08-2021	दिल्ली सरकार बनाम भारत संघ
38134 / 2009	सिविल अपील / 1214 / 2011	11-12-2009	भारत संघ बनाम विनोद कुमार
1543 / 2016	रिट याचिका (सिविल) / 36 / 2016	12-01-2016	वी. वसंतकुमार बनाम एच.सी. भाटिया और अन्य, विधि और न्याय मंत्रालय
27156 / 2016	रिट याचिका(आपराधिक) / 113 / 2016	12-08-2016	कौशल किशोर बनाम उत्तर प्रदेश सरकार उ.प्र. गृह

28033 / 2005	सिविल अपील / 7513 / 2005	14-12-2005	आ.प्र. राज्य बनाम बी. अर्चना रेड्डी।
29686 / 2017	सिविल अपील / 841 / 2018	16-09-2017	मेसर्स बजाज एलायंस जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम रम्भा देवी
42134 / 2016	विशेष अनुमति याचिका (सिविल) / 804 / 2017	17-12-2016	कर्मण्य सिंह सरिन बनाम भारत संघ
76079 / 1996	सिविल अपील / 16879 / 1996	18-12-1996	पश्चिम बंगाल राज्य बनाम पश्चिम बंगा बी.के. समिति।
16155 / 2022	-	19-05-2022	चेन्नोलु लीला प्रसाद राव बनाम सोमेश कुमार
47928 / 2023	आपराधिक अपील / 3589 / 2023	19-11-2023	हाई कोर्ट बार एसोसिएशन इलाहाबाद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य
13164 / 2011	सिविल अपील / 2634 / 2013	21-04-2011	तेज प्रकाश पाठक बनाम राजस्थान उच्च न्यायालय
38037 / 2022	-	23-11-2022	जया ठाकुर बनाम भारत संघ
16113 / 2009	रिट याचिका (सिविल) / 274 / 2009	25-05-2009	नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6क के संदर्भ में बनाम....
23064 / 2018	सिविल अपील / 9228 / 2022	26-06-2018	हरिहरन बनाम हर्ष वर्धन सिंह राव
10061 / 2017	स्थानांतरण याचिका (सिविल) / 582 / 2017	30-03-2017	खुडाला ग्राम सेवा सरकार समिति लिमिटेड बनाम भारत संघ
21589 / 2005	आपराधिक अपील / 375 / 2006	30-09-2005	भारत संघ बनाम प्रीति अग्रवाल
सात न्यायाधीशों की पीठ			
/ 2021	रिट याचिका (सिविल) / 682 / 2021	24-06-2021	एस.जी. वोम्बटकेरे बनाम भारत संघ
15235 / 2015	विशेष अनुमति याचिका (सिविल) / 14842 / 2015	07-05-2015	रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय ए बनाम तमिलनाडु लोक सेवा आयोग
20234 / 2022	रिट याचिका (सिविल) / 493 / 2022	08-07-2022	सुभाष देसाई बनाम प्रधान सचिव, महाराष्ट्र के राज्यपाल
23338 / 2003	रिट याचिका(आपराधिक) / 206 / 2003	09-11-2003	एन. रवि बनाम अध्यक्ष, विधान सभा, चेन्नई और अन्य
25536 / 2010	सिविल अपील / 2317 / 2011	13-08-2010	पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह
71852 / 1994	सिविल अपील / 8763 / 1994	11-02-1994	अर्जुन फ्लोर मिल्स बनाम ओडिशा राज्य वित्त विभाग का गुप्त
9287 / 2006	सिविल अपील / 2286 / 2006	08-04-2006	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अपने रजिस्टर के माध्यम से बनाम नरेश अग्रवाल
9680 / 2017	सिविल अपील / 8588 / 2019	28-03-2017	रोजर मैथ्यू बनाम साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड और अन्य मुख्य प्रबंधक
नौ न्यायाधीशों की पीठ			
2996 / 2005	सिविल अपील / 151 / 2007	05-07-2005	उत्तर प्रदेश राज्य बनाम मेसर्स लालता प्रसाद वैश्य
16528 / 2001	रिट याचिका (सिविल) / 419 / 2001	24-09-2001	अहमद हबीब भारतीय निवासी बनाम महाराष्ट्र राज्य सचिव के माध्यम से
28032 / 2006	सिविल अपील / 673 / 2008	01-11-2006	उत्तर प्रदेश राज्य बनाम मेसर्स केसर एंटरप्राइजेज लिमिटेड
38452 / 2018	पुनर्विलोकन याचिका (सिविल) / 3358 / 2018	10-10-2018	कांतारू राजीवारू बनाम इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन के महासचिव के माध्यम से
78629 / 1992	सिविल अपील / 1012 / 2002	31-12-1992	संपत्ति मालिक संघ बनाम महाराष्ट्र राज्य।
9012 / 1999	सिविल अपील / 4056 / 1999	26-05-1999	खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकरण आदि बनाम मेसर्स स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया।

9099 / 2001	सिविल अपील / 897 / 2002	24-05-2001	उत्तर प्रदेश राज्य बनाम जयबीर सिंह
-------------	----------------------------	------------	------------------------------------
